सिविल विविध

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन और एच. आर. सोढ़ी के समक्ष

जगतर सिंह – याचिकाकर्ता

बनाम

अधीक्षण नहर अधिकारी और ओथेब्स- ***उत्तरदाता।***

1971 की सिविल रिट संख्या 1350

15 सितंबर, 1971

*उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (*1873 *का VIII) - धारा 30-एफएफ - धारा द्वारा विचार किए गए जल-मार्गों के प्रकार - कहा गया है - किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि पर अनधिकृत जल-मार्ग की खुदाई - ऐसा व्यक्ति जो जलमार्ग को नष्ट कर रहा है* - धारा *30-एफएफ - चाहे वह आकर्षित हो।*

माना जाता है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम, 1873 की धारा 30-एफएफ तीन प्रकार के जल-पाठ्यक्रमों पर विचार करती है: (ए) कानून द्वारा स्वीकृत; (ख) वे जो पक्षों के बीच हुए समझौते द्वारा स्वीकृत किए गए हैं; और (ग) जिन्हें सरलता के माध्यम से निर्धारित किया गया है। इन तीन प्रकार के जल-पाठ्यक्रमों के मामले में पानी को रोकने के बाद ही अधिनियम की धारा 30-एफएफ लागू होगी। जहां किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति के बिना

उसकी भूमि पर अनधिकृत जल-मार्ग खोदा जाता है, जिसे बाद में उस व्यक्ति द्वारा ध्वस्त कर दिया जाता है, तो ऐसा जल-मार्ग धारा 30-एफएफ के दायरे में नहीं आएगा, भले ही इसका उपयोग कुछ वर्षों के लिए किया गया हो। कोई भी कानून किसी अवैध कार्य को जारी रखने पर विचार नहीं करता है या किसी अवैध कार्य को वैधता नहीं देता है क्योंकि यह बार-बार किया गया है। अधिनियम की धारा 30-एफएफ का सहारा लेकर अवैधता को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 6)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के *तहत याचिका* में अनुरोध किया गया है कि 29 *मार्च, 1971 के आक्षेपित आदेश* (अनुलग्नक 'सी'*) को रद्द करते हुए कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से *पी.एस., जैन और वी.एम.जैन ने दलीलें दीं।*

अशोक भान, वकील, प्रतिवादी *1* और *2* के लिए।

एस. के. पिपट। वकील, प्रतिवादी 3 के लिए।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था :-

न्यायमूर्ति महाजन - (1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और

227 के तहत एक याचिका है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उत्तरी भारत नहर और जल निकासी अधिनियम (1873 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 30-एफएफ (4) के तहत अपील में पारित अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया जाए।

(2) इसे एक बड़ी पीठ के समक्ष स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रवेश करने वाली पीठ ने उम्मेद सिंह बनाम हरियाणा राज्य[1] में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की सत्यता के बारे में कुछ संदेहों पर विचार किया ।

(3) तथ्य सरल हैं और किसी भी विवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, स्वीकृत वाटरकोर्स निश्चित रूप से 'एबीसीडी' था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने 25 अप्रैल, 1971 को अधीक्षण नहर अधिकारी की वापसी के साथ दायर योजना पर एबीसीडी अक्षरों द्वारा निरूपित एक वाटरकोर्स में बिंदु 'ए' से अपना पानी लेना शुरू कर दिया। वर्तमान याचिका दायर होने से कुछ साल पहले, याचिकाकर्ता वाटरकोर्स 'एबीसीडी' में बिंदु ए से पानी ले रहा था। बिंदु ए से बी तक भूमि के मालिकों ने जलमार्ग को ध्वस्त कर दिया। इसके कारण याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 30एफएफ के तहत संभागीय नहर अधिकारी को आवेदन दिया। संभागीय नहर अधिकारी ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से जिलेदार से रिपोर्ट मांगी। जिलेदार ने बताया कि बिंदु ए और बी के बीच के जलमार्ग को इस परिणाम के साथ ध्वस्त कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की फसलों को नुकसान हो रहा था और

[1] 1970 P.L.J. 503

उन्होंने सिफारिश की कि इसे पुलिस की मदद से बहाल किया जाए। इस सिफारिश को उपखंड अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और इसका समर्थन करते हुए कागजात संभागीय नहर अधिकारी को भेज दिए। इसके बाद संभागीय नहर अधिकारी ने पुलिस की मदद से वाटरकोर्स 'एबीसीडी' को बहाल करने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ प्रतिवादी ने अपील की थी, जो वाटरकोर्स 'एबी' से लगी जमीन का मालिक है। अधीक्षण नहर अधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील की अनुमति दी

उन्होंने कहा, 'संभागीय नहर अधिकारी ने वाटरकोर्स 'एबी' को बहाल करने का आदेश दिया था। *इस आउटलेट की वारबंदी* को वर्ष 20 दिसंबर, 1966 के दौरान धारा 68 के तहत मंजूरी दी गई थी। स्वीकृत *वरबंदी* के साथ संलग्न मानचित्र देखा गया है और यह पाया गया है कि वाटरकोर्स 'एबी' खेती के समय मौजूद नहीं था।"

दूसरे शब्दों में, अधीक्षण नहर अधिकारी द्वारा अपनाया गया आधार यह प्रतीत होता है कि चूंकि जलमार्ग 'एबीसीडी' अधिकृत नहीं है, इसलिए धारा 30-एफएफ के तहत इसकी बहाली नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता की फसलों की सुरक्षा के लिए, उन्होंने 15 अप्रैल, 1971 तक वाटरकोर्स 'एबीसीडी' के उपयोग की अनुमति दी। अधीक्षण नहर अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस न्यायालय का रुख किया है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलील उम्मेद सिंह के मामले में एडी कोशल, जे के फैसले पर आधारित है इस मामले में धारा 30-क के उपबंधों को निर्धारित

करने के बाद यह पाया गया था - '

"खंड (ए) में उपयोग किए गए शब्द एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं और इसका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि सभी प्रकार के जलमार्ग, स्वीकृत या अस्वीकृत, उनके द्वारा विचार किए जाते हैं।"

इस निर्णय के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अधीक्षण नहर अधिकारी का निर्णय कानून में गलत है और उनके पास डिवीजनल नहर अधिकारी के फैसले में इस आधार पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि वाटरकोर्स 'एबी' एक अधिकृत वाटरकोर्स नहीं था।

(5) विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं। विद्वान एकल न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, जिन्होंने यह विचार लिया है कि एक अनधिकृत जलमार्ग धारा 30-ए या धारा 30-एफएफ द्वारा कवर किया गया है, हम सहमत होने में असमर्थ हैं। इससे पहले कि हम इस प्रश्न से निपटें, अधिनियम की धारा 3(2) का उल्लेख करना उचित होगा जो निम्नलिखित शब्दों में जलमार्ग को परिभाषित करती है -

"वाटरकोर्स" का अर्थ है कोई भी चैनल जिसे नहर से पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जिसका रखरखाव राज्य सरकार की कीमत पर नहीं किया जाता है, और ऐसे किसी भी चैनल से संबंधित सभी सहायक कार्य हैं।"

धारा 3 (1) 'नहर' को "इस खंड के दूसरे खंड में परिभाषित सभी जलमार्गों" के रूप में परिभाषित करती है। अधिनियम की धारा 30-ए, 30एफएफ और धारा 70 के प्रासंगिक भागों को निर्धारित करना भी उचित होगा। उन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"30-A. (1) इस अधिनियम में इसके विपरीत निहित किसी बात के होते हुए और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन रहते हुए, संभागीय नहर अधिकारी, स्वयं के प्रस्ताव पर या शेयरधारक के आवेदन पर, सभी या किन्हीं विषयों के लिए प्रावधान करने के लिए एक प्रारूप योजना तैयार कर सकता है, अर्थात्:-

(a) किसी भी जलमार्ग का निर्माण, परिवर्तन, विस्तार और संरेखण या किसी भी मौजूदा जलमार्ग का पुन: संरेखण;

(b) एक जलमार्ग द्वारा दूसरे जलमार्ग को प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों का पुन: आवंटन;

(c) किसी भी जलमार्ग की परत;

(cc) जलमार्ग मंजूरी से मिट्टी जमा करने के लिए भूमि का कब्जा;

(d) कोई अन्य मामला जो एक जलमार्ग से पानी की आपूर्ति के उचित रखरखाव और वितरण के लिए आवश्यक है

30-FF. (1) यदि कोई व्यक्ति किसी जलमार्ग को ध्वस्त करता है, बदल देता है, बड़ा करता है या बाधित करता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है,

तो प्रभावित कोई भी व्यक्ति जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश देने के लिए डिवीजनल नहर अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रभागीय नहर अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे, इस प्रकार ध्वस्त करने, परिवर्तन करने, विस्तार करने, बाधा डालने या क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्ति को लिखित में दिए गए नोटिस द्वारा अपनी लागत पर उस जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने की अपेक्षा कर सकता है, जैसा कि नोटिस में विनिदष्ट किया जाए।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति उपधारा (2) के तहत उसे दिए गए नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में डिवीजनल नहर अधिकारी की संतुष्टि में विफल रहता है, तो डिवीजनल नहर अधिकारी जलमार्ग को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर सकता है और चूककर्ता व्यक्ति से ऐसी बहाली के संबंध में किए गए खर्च की वसूली कर सकता है।

70. जो कोई भी, उचित अधिकार के बिना और स्वेच्छा से, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है, अर्थात्-

(1) किसी भी नहर या जल निकासी कार्य को नुकसान पहुंचाता है, बदलता है, बढ़ाता है या बाधित करता है;

(2) किसी भी नहर या जल निकासी कार्य के माध्यम से, उसके माध्यम से या नीचे पानी की आपूर्ति में हस्तक्षेप करता है, बढ़ाता है या कम करता है;

दंड-ऐसे वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर, जैसा कि राज्य सरकार इस निदेश देती है, 100 रुपये से अधिक का जुर्माना या एक माह से अधिक का कारावास या दोनों हो सकता है।"

(6) इन सांविधिक उपबंधों के आलोक में इस प्रश्न की जांच की जानी चाहिए कि क्या धारा 30-एफएफ के उपबंधों में अनधिकृत जलमार्ग शामिल है? जहां तक अधिनियम का संबंध है, यह प्राधिकृत और अनधिकृत दोनों जलमार्गों से संबंधित है। हम 'अधिकृत वाटरकोर्स' शब्द का उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराए गए वाटरकोर्स के लिए कर रहे हैं, अन्य सभी अनधिकृत हैं। लेकिन एक वाटरकोर्स के बीच अंतर की एक दुनिया है जिसे किसी क़ानून के तहत या समझौते द्वारा या नुस्खे द्वारा अधिकार के मामले के रूप में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक ऐसा जलमार्ग शामिल नहीं किया जा सकता जिसका कोई वैध अस्तित्व नहीं है। इसमें एक जलमार्ग भी शामिल हो सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि से होकर गुजरता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति इसे जलमार्ग के रूप में उपयोग किए जाने पर आपत्ति नहीं करता है, लेकिन, हमारी राय में, एक जलमार्ग जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर उसकी अनुमति के बिना उपयोग किया गया है, अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। यदि न्याय कोष का निर्णय यह बताता है कि अधिनियम केवल उन जलमार्गों से संबंधित है जो उसके द्वारा अधिकृत हैं या जो अधिनियम द्वारा अनधिकृत हैं, लेकिन अन्यथा अधिकृत हैं, जैसा कि ऊपर

निर्धारित किया गया है, तो इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। लेकिन यदि यह निर्णय आगे बढ़ता है और उस प्रकार के जलमार्गों को गले लगाता है जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, अर्थात्, उसकी अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर एक जलमार्ग, तो निश्चित रूप से निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हम विद्वान न्यायाधीश के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ ऐसा कहते हैं। कोई भी कानून किसी अवैध कार्य को जारी रखने पर विचार नहीं करता है या किसी अवैध कार्य को वैधता नहीं देता है क्योंकि यह बार-बार किया गया है। हमने इस मामले पर जो दृष्टिकोण अपनाया है, उसे *हुकमान* बनाम *सम्राट*[2] में लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। इस फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है और संदर्भ केवल *मूला सिंह* बनाम *सुरेंद्र सिंह*[3] को दिए जाने की जरूरत है , जिसमें एक ही दृष्टिकोण लेने वाले कई फैसलों को इकट्ठा किया गया है। यह सच है कि लाहौर का फैसला धारा 70 के प्रावधानों से संबंधित है, लेकिन मोटे तौर पर, उस धारा और धारा 30-एफएफ का दायरा परी *मटेरिया है।*उदाहरण के लिए, धारा 70 (1) परिवर्तन, वृद्धि या बाधा की बात करती है जबकि धारा 30-एफएफ (1) भी परिवर्तन, वृद्धि और बाधा की बात करती है। धारा 70 1921 में लाहौर उच्च न्यायालय में व्याख्या के लिए गिर गई और यह फैसला सुनाया गया कि यह केवल तीन प्रकार के जलमार्गों पर विचार करता है, अर्थात –

(a) कानून द्वारा स्वीकृत;

(b) पार्टियों के बीच समझौते द्वारा स्वीकृत; और

(c) जिन्हें सरलता के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

[2] A.I.R. 11921 Lah. 327.
[3] A.I.R. 1960 All. 656

यह भी माना गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की भूमि के माध्यम से पानी लेता है, तो दूसरे व्यक्ति को अपनी भूमि के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोकने का अधिकार है, जिससे धारा 70 के अर्थ के भीतर कोई अपराध नहीं किया जा सकता है। यह केवल तभी होता है जब पहले से ही उल्लिखित तीन प्रकार के जलमार्गों के मामले में पानी बंद हो जाता है, कि धारा 70 लागू हो जाएगी- इसलिए, एक वाटरकोर्स जो ऊपर दिए गए वाटरकोर्स के विवरण का उत्तर नहीं देता है, वह निश्चित रूप से धारा 70 और धारा 30-एफएफ के दायरे से बाहर होगा। धारा 70 की न्यायिक व्याख्या के लंबे समय बाद धारा 30-एफएफ को कानून की किताब में लाया गया है और हमें करना चाहिए। इस आधार पर आगे बढ़ें कि धारा 30-एफएफ के किसानों को पता था कि धारा 70 की व्याख्या कैसे की गई थी और जहां भी उन्होंने धारा 30-एफएफ में एक ही भाषा का उपयोग किया है, उसमें एक ही व्याख्या होनी चाहिए और कोई अन्य नहीं।

(7) उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता को एक उदाहरण का उल्लेख करके प्रदर्शित किया जा सकता है जहां एक पक्ष द्वारा एक अनधिकृत जलमार्ग खोदा जाता है और वह उस जलमार्ग में नहर से पानी खींचता है। निश्चित रूप से, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि इस तरह का वाटरकोर्स धारा 30-एफएफ के दायरे में आएगा। यदि ऐसा है, तो हम यह नहीं देखते कि रेखा कहां खींची जाए, क्योंकि इसमें भी, सभी अवैध जलमार्ग धारा 30-एफएफ के दायरे में आएंगे और उस अवैधता को रोकने का कोई तरीका नहीं होगा क्योंकि अवैधता को कानून की मंजूरी प्राप्त होगी

क्योंकि इसे धारा 30-एफएफ का सहारा लेकर कायम रखा जा सकता है।

(8) इसके बाद श्री जैन ने यह तर्क उठाया कि वाटरकोर्स 'एबी' को समझौते द्वारा मंजूरी दी गई है। रिकॉर्ड पर कोई समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान वकील को इस तर्क के लिए प्रेरित किया गया कि क्योंकि जलमार्ग दो साल की अवधि के लिए उपयोग में था, इसलिए हमें इससे एक समझौता करना चाहिए। हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं। *लाहौर मामले* (2) में, जिसे पहले ही संदर्भित किया गया था, जलमार्ग 13 वर्षों से अस्तित्व में था और अभी भी कोई समझौता नहीं किया गया था। उपयोगकर्ता के एक लंबे पाठ्यक्रम के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता को पर्चे द्वारा परिपूर्ण बनाया जा सकता है, लेकिन इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, जिस भूमि में चैनल 'एबी' मौजूद है, उसके मालिकों ने इस बात से इनकार किया है कि वे याचिकाकर्ता द्वारा इसके उपयोगकर्ता से सहमत थे। दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता गुप्त तरीके से इस चैनल का उपयोग कर रहा है। हालांकि, हम इस विवाद से चिंतित नहीं हैं क्योंकि, हमारी राय में, रिकॉर्ड पर कोई समझौता साबित नहीं हुआ है जो धारा 30-एफएफ के तहत डिवीजनल नहर अधिकारी द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा।

(9) जैन ने तब तर्क दिया कि जल-चैनल 'एडीईएफजीएच' प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता की भूमि तक पानी नहीं ले जाता है। उनका तर्क है कि पानी ठीक से बिंदु 'जी' तक चलता है, लेकिन बिंदु 'जी' से परे याचिकाकर्ता की भूमि पर पानी का चलना बहुत मुश्किल है। यदि ऐसा है, तो याचिकाकर्ता का उचित उपाय इस चैनल

के उचित पुनर्गठन के लिए नहर अधिकारियों से संपर्क करना है; दूसरे शब्दों में, चैनल के परिवर्तन या पुनर्गठन के लिए। यह टिंडर धारा 30-एफएफ की अनुमति है। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है और शिकायत वास्तविक है, तो हमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता के लिए निवारण उपलब्ध होगा, लेकिन वह वर्तमान कार्यवाही में यह दावा नहीं कर सकता है कि वह 'एबी' चिह्नित वाटरकोर्स के उपयोगकर्ता का हकदार है। हमारी राय में, अधीक्षण नहर अधिकारी का निर्णय सही था और इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(10) इस समय याचिकाकर्ता के रास्ते में कठिनाई यह है कि 'जी से एच' चिह्नित चैनल अब उसके लिए उपलब्ध नहीं है और उसकी फसल की सुरक्षा के लिए, हम निर्देश देते हैं कि उसे छह महीने की अवधि के लिए वाटरकोर्स 'एबी' का उपयोग करने की अनुमति दी जाए ताकि वह उसे निवारण देने के लिए नहर अधिकारियों से संपर्क कर सके।

(11) दर्ज किए गए कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है। मुआवज़े के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के

लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा